

[2023] 5 एस. सी. आर 503

हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर।

बी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 237)

13 फरवरी, 2023

[संजय किशन कौल और अभय एस. ओका, जेजे।]

भारत का संविधान-कला। 170 और 239 ए-जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 - एस. 13-कला। 170 "राज्य विधानमंडल" शीर्षक के तहत संविधान के भाग VI के अध्याय III का हिस्सा बनाना-कला की प्रयोज्यता का मुद्दा। 170 केंद्र शासित प्रदेश J & K के लिए-आयोजित: जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान सभा का संबंध है, अनुच्छेद। 170 नहीं होगा।

आवेदन क्योंकि यह भाग VI के अध्याय III का एक हिस्सा है जो संबंधित है

केवल राज्य विधानमंडल के साथ-इसका केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है-इसका कारण यह है कि संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएँ संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा Art.239A के अनुसार शासित होंगी, न कि भाग VI के अध्याय III के प्रावधानों द्वारा-S के आधार पर। 13 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, अनुच्छेद। 239 ए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए लागू हो गया।

परिसीमन अधिनियम, 2002 - धारा 9-जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019। 60 और 62-परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक परिसीमन आयोग के गठन की कार्रवाई और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन का अभ्यास-आयोजित सीटों की वैधता और वैधता का पुनः समायोजन: जे एंड के का भाग 5 पुनर्गठन अधिनियम उप-धारा (1) के खंड (ए) के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। 62 , परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को संघ पर लागू किया गया था

31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र-एस की उप-धारा (1)। 60 यह प्रावधान है कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश को 90 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित करने और आरक्षण प्रदान करने की कवायद चुनाव द्वारा की जा सकती है।

कमीशन-हालाँकि, एस का उद्देश्य। 62 यह है कि यदि परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, एस की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (सी) द्वारा प्रदान किया गया अभ्यास। 60

[2023] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा-धाराओं की उप-धारा (2)। 62 निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन को संदर्भित करता है-एस की उप-धारा (2) का उद्देश्य। 62 यह है कि पुनः समायोजन का अर्थ है नव स्थापित केंद्र शासित प्रदेश में 90 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण।

एस की उप-धारा (2) द्वारा विचारित पुनः समायोजन की प्रक्रिया। 62 एस की उप-धारा (1) के तहत परिसीमन के अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं है। 60 .

परिसीमन अधिनियम, 2002 - एस. 9 एस. 9 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 62 और 63-का संविधान

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के लिए परिसीमन आयोग और कश्मीर-2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन/पुनः समायोजन का अभ्यास -

आयोजित किया गया: एस की उप-धारा (1) के खंड (बी) के आधार पर। 62 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, वर्ष 2001 की धाराओं की उप-धारा (1) में दिखाई देता है। 9 परिसीमन अधिनियम, 2002 को 2011 के रूप में पढ़ना होगा-इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश को 90 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के उद्देश्यों के लिए परिसीमन आयोग द्वारा किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन/पुनः समायोजन के अभ्यास के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है

2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर-एस की उप-धारा (1) का खंड (बी)। 62 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने परिसीमन अधिनियम, 2002 में यह प्रावधान करते हुए संशोधन किया कि परिसीमन अधिनियम में आने वाले शब्द और आंकड़े 'वर्ष 2001 में आयोजित जनगणना' का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा -

' वर्ष 2011 में आयोजित जनगणना-संघ में इसके आवेदन के लिए

जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र, एस की उप-धारा (1) में वर्ष 2001। 9 परिसीमन अधिनियम, 2002 को वर्ष 2011 तक प्रतिस्थापित कर दिया गया है और इसलिए, लोक सभा में सीटों के वितरण और विधानसभा को आवंटित सीटों को 2011 की जनगणना के आधार पर फिर से समायोजित करना होगा और परिसीमन वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। 63 यह है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजन/परिसीमन की कवायद होने के बाद, 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों तक इसे रोक दिया जाएगा।

उपलब्ध-इसलिए, परिसीमन/पुनः समायोजन का अभ्यास

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सीटें परिसीमन आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जानी आवश्यक थी। 63 , वर्ष 2026 के बाद आयोजित जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद ही पुनः समायोजन किया जा सकता है।

हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

परिसीमन अधिनियम, 2002-ss. 10 एसएस। 10 ((6 6)) और 10 ए 10 ए-जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 - एस. 62-ए के गठन की कार्यवाही

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग-परिसीमन अभ्यास-समय सीमा एस. 10 (6)-यदि अनिवार्य है-आयोजित: अधिनियम, 2002 का s.10A स्वयं इंगित करता है कि धाराओं की उप-धारा (6) के तहत 31 जुलाई 2008 की समय सीमा निर्धारित की गई है। 10 यह पवित्र नहीं है क्योंकि यह माननीय राष्ट्रपति को स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है

एस. 10 एस में संशोधन करते समय कभी भी अनिवार्य होने का इरादा नहीं था। 2 (च) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा परिसीमन अधिनियम की धाराओं की उप-धारा (6)। 10 इसके तहत प्रदान की गई अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधन नहीं किया गया है-हालाँकि, विधायिका का इरादा जैसा कि परिलक्षित होता है एस की उप-धारा (2) और (3) में। 62 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का स्पष्ट तथ्य यह है कि उप-धाराओं (2) और (3) के अनुसार पुनः समायोजन करने का कर्तव्य है। 62 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग को सौंपा गया है कि विधायिका का इरादा है कि परिसीमन

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए आयोग जुलाई 2008 के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता से अप्रभावित रहेगा। 62 यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विधायिका धाराओं की उप-धारा (6) में प्रदत्त समय सीमा को संशोधित करने में विफल रही है तो इसकी व्याख्या इस तरीके से करनी होगी जो विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाती है। 10 परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त करने में असमर्थ है। 62 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को निरर्थक बना दिया जाएगा।

परिसीमन अधिनियम, 2002-परिसीमन आयोग

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर-परिसीमन आयोग के अध्यक्ष-अध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल

6 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत,

परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, जो इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, एक वर्ष की अवधि के लिए थे-3 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को दो वर्ष तक बढ़ा दिया गया था -

21 फरवरी 2022 की तीसरी विवादित अधिसूचना, दो साल की उक्त अवधि को दो साल और दो महीने तक बढ़ा दिया गया था: एक बार परिसीमन आयोग की स्थापना के बाद, 5 एस. सी. आर. [2023] है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि केंद्र सरकार ने परिसीमन/पुनः समायोजन का कार्य पूरा होने तक अध्यक्ष की नियुक्ति की अवधि बढ़ा दी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है-परिसीमन अधिनियम, 2002 अध्यक्ष की नियुक्ति के कार्यकाल के बारे में चुप है।

भारत का संविधान-कला। 3 , 4 और 239 ए-किसी मौजूदा राज्य का एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में रूपांतरण-राज्य की शक्ति संसद-कला का संयुक्त अध्ययन। 3,4 और 239 ए-आयोजित:

संसद एक कानून बनाकर किसी मौजूदा राज्य को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर सकती है।

अभ्यास और प्रक्रिया-एक कानून की संवैधानिक वैधता

- चुनौती के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए-आयोजित: जब कोई पक्ष किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहता है, तो उसे विस्तार से उन आधारों का अनुरोध करना चाहिए जिन पर कानून की वैधता को चुनौती दी जानी चाहिए-संवैधानिक न्यायालय विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि इसे विशिष्ट आधारों को शामिल करके विशेष रूप से चुनौती नहीं दी जाती है।

अभिवचनों में चुनौती-इसका कारण यह है कि कानूनों की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा होता है-बोझ हमेशा होता है

इसे साबित करने के लिए असंवैधानिकता का आरोप लगाने वाला व्यक्ति-ए

संवैधानिक न्यायालय किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में केवल इन दलीलों से निष्कर्ष निकालकर आकस्मिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि वैधता को चुनौती निहित है।

आयोजित कानूनों की व्याख्या: एक कानून नहीं हो सकता है

इस तरह से व्याख्या की जाए जो इसके कुछ प्रावधानों को अनुचित बना दे-एक कानून का इस तरह से अर्थ लगाया और व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इसे व्यवहार्य बनाया जा सके।

सिद्धांत/सिद्धांत-समानता-दो असमानों को समान नहीं माना जा सकता है।

शब्द और वाक्यांश शब्द "प्रयास"-एस के उप-खंड (6) में शब्द का उपयोग। 10 परिसीमन अधिनियम, 2002।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. संघ को "विधान सभाओं की संरचना" शीर्षक वाले अनुच्छेद 170 के लागू होने का मुद्दा

जे एंड के का क्षेत्र।

1.1 . अनुच्छेद 170 "राज्य विधानमंडल" शीर्षक के तहत अध्याय III का हिस्सा है। अध्याय III को हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर. में शामिल किया गया है।

संविधान का भाग VI जो राज्यों से संबंधित है। यद्यपि याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे प्रावधान में निहित प्रावधानों के उल्लंघन पर बहुत जोर दिया गया था, लेकिन उक्त अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 239 ए और 239 एए जो संविधान के भाग VIII में शामिल हैं वे अनुच्छेद हैं जो विधायिका के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय के निर्माण से संबंधित हैं और

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्री परिषद। [पैरा 18] [532 बी-डी]

1.2 . अनुच्छेद 239 ए, जैसा कि यह मूल रूप से था, प्रदान करता है कि संसद कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए बना सकती है -

पुडुचेरी संघ के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाला एक निकाय है क्षेत्र या मंत्रिपरिषद या दोनों। अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत आने वाले केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाला ऐसा निकाय

निर्वाचित या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13 के आधार पर, अनुच्छेद 239 ए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गया। जैसा कि अनुच्छेद 239 ए के खंड (2) में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 239 ए के खंड (1) द्वारा अनुध्यात कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही इसमें कोई भी प्रावधान हो जो संविधान में संशोधन करता हो या जिसका संविधान में संशोधन करने का प्रभाव हो। [पैरा 18] [532-जीएच; 533-ए-बी]

संघ के लिए विधायिका का एक निकाय बनाने के लिए कानून द्वारा सशक्त पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र। तदनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए एक विधानसभा होगी।

के. ; और (ग) भले ही पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल का निकाय बनाने के लिए संसद द्वारा बनाई गई कानून का संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करने का प्रभाव है, लेकिन इसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। [पैरा 19] [533-बी-ई]

1.4 . जहां तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का संबंध है, अनुच्छेद 170 में कोई [2023] 5 एस. सी. आर. नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन क्योंकि यह भाग VI के अध्याय III का एक हिस्सा है जो संबंधित है

केवल राज्य विधानमंडल के साथ। यह केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों पर लागू नहीं होता है। इसका कारण यह है कि संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं अनुच्छेद 239 ए के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा शासित होंगी, न कि भाग VI के अध्याय III के प्रावधानों द्वारा। चूंकि अनुच्छेद 170 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विधानमंडल पर लागू नहीं होता है, इसलिए इस तर्क का मुख्य जोर कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कुछ प्रावधान और उसके तहत की गई कार्रवाई अनुच्छेद 170 और विशेष रूप से खंड (3) के साथ टकराव में हैं, स्पष्ट रूप से गलत धारणा है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। [पैरा 23] [534-डी-एफ]

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का मुद्दा।

2.1 . परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित पहले के दो अधिनियम थे। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 और दूसरा परिसीमन अधिनियम, 1972 था। दोनों अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थे क्योंकि दोनों अधिनियमों में शामिल राज्य की परिभाषा में विशेष रूप से जम्मू राज्य को शामिल नहीं किया गया था

और कश्मीर। परिसीमन अधिनियम, 2002 का भी यही हाल है। जे एंड के आर. पी. अधिनियम की धारा 3 ने आवश्यकता निर्धारित की

परिसीमन आयोग की स्थापना जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि परिसीमन आयोग विधान सभा में एकल सदस्य क्षेत्रीय को सीटें वितरित करेगा।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए

2.2 . जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (5) के आधार पर 1995 का उक्त परिसीमन आदेश था - उसकी तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार संशोधन किया गया। तीसरी अनुसूची में संशोधनों का विवरण है -

उक्त हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर. द्वारा बनाए गए विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन।

मौजूदा 83 विधानसभाओं के संबंध में 1995 का परिसीमन आदेश

धारा 14 की उप-धारा (3) में उपबंधित कुल 107 निर्वाचन क्षेत्रों में से। पाकिस्तान के कब्जे वाले 24 निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिसीमन आदेश द्वारा कवर नहीं किए गए थे। इस प्रकार, धारा 14 की उप-धारा (5) के आधार पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के 83 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तीसरी अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था।

2.3 . जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का भाग 5 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। उपखंड (क) के आधार पर परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 62 की धारा (1) के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू किए गए थे। [पैरा 26] [535-एफ-जी]

2.4 . केंद्र शासित प्रदेश के 83 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था और इसे तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया था जैसा कि उप-धारा में दिया गया है। (5) धारा 14। धारा 60 की उप-धारा (1) के अधिदेश के आधार पर, विधान सभा में सीटों की कुल संख्या

केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को 107 से बढ़ाकर 114 करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से 24 सीटों को छोड़कर, जनादेश सीटों को 83 से बढ़ाकर 90 करना था। उपरोक्त सीटों की संख्या में वृद्धि को प्रभावी बनाने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश को 90 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने और सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए परिसीमन की कवायद

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना आवश्यक था करने के लिए। धारा 60 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि उक्त परिसीमन की कवायद चुनाव द्वारा की जा सकती है।

आयोग। हालांकि, धारा 62 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर के उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेश में धारा 60 के तहत विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत गठित किए जाने वाले परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। धारा 60 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश को 90 विधानसभा क्षेत्रों और [2023] 5 एस. सी. आर. में विभाजित करने की कवायद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम 2002, धारा 60 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (सी) द्वारा प्रदान किया गया अभ्यास परिसीमन द्वारा किया जाएगा। आयोग। तथापि, धारा 62 की उप-धारा (2) निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन को संदर्भित करती है। लेकिन, धारा 62 की उप-धारा (2) का उद्देश्य यह है कि पुनः समायोजन का अर्थ है नव स्थापित केंद्र शासित प्रदेश में 90 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण। इस प्रकार, धारा 62 की उप-धारा (2) द्वारा अनुध्यात पुनः समायोजन की प्रक्रिया धारा 60 की उप-धारा (1) के तहत परिसीमन के प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है। [पैरा 27] [539-ए-एफ]

2.5 . परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधान इंगित करते हैं

पुनः समायोजन क्या है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के आधार पर, वर्ष 2001 को विधान के संबंध में वर्ष 2011 तक प्रतिस्थापित किया गया है।

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 के तहत परिसीमन आयोग को परिसीमन के संचालन के लिए एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है व्यायाम करें। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के आधार पर, वर्ष 2001 उप-खंड में दिखाई देता है।

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 की धारा (1) को 2011 के रूप में पढ़ना होगा। इसलिए, परिसीमन आयोग 6 मार्च 2020 के आदेश के तहत स्थापित, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन या पुनः समायोजन का अभ्यास करना था क्योंकि पूर्ववर्ती राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अभ्यास 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नहीं किया गया था। ऊपर बताए गए कारणों के लिए, के अभ्यास के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है

निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के उद्देश्यों के लिए परिसीमन आयोग द्वारा किए गए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन/पुनः समायोजन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 90 निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश। [पैरा 28 और 29] [539-जी; 540-डी-ई; 541-एफ-एच; 542 ए]

2.6 . 1950 के आर. पी. अधिनियम की पहली अनुसूची में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को कुल 6 सीटें आवंटित की गई थीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं।

हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि पूर्ववर्ती राज्य को आवंटित 6 सीटों में से 5 सीटें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को आवंटित की जाएंगी और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दी जाएगी। इस प्रकार धारा 11 में यह प्रावधान है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार संशोधित किया गया है। इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन दूसरी अनुसूची में प्रदान की गई धारा 11 के आधार पर किया गया था। [पैरा 30] [542-बी-डी]

2.7 . जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) के खंड (सी) में प्रावधान है कि विधान सभा की सीटों की संख्या, सीमाओं में समायोजन और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का विवरण

चुनाव आयोग। धारा 62 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेशों में धारा 11 में दिए गए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्व्यवस्थापन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। द.

धारा 62 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थापन, धारा 60 की उप-धारा (1) में दिए गए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का समायोजन और विस्तार का विवरण है। 90 निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन/परिसीमन की आवश्यकता के परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया।

विधान सभा। इसलिए, संसदीय परिसीमन/पुनः समायोजन से कोई अवैधता जुड़ी नहीं है।

6 मार्च 2020 की अधिसूचना द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की वैधता 3.1 . जब परिसीमन आयोग का गठन करने वाली 6 मार्च 2020 की विवादित अधिसूचना की आवश्यकता होती है

परिसीमन आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अभ्यास करने के लिए, यह धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) में प्रदान किए गए पुनर्संगठन के अभ्यास को संदर्भित करता है जो कि [2023] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधानसभा की सदस्यता 83 से बढ़ाकर 90 करने के कारण धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा परिसीमन अभ्यास पर विचार किया गया है। इसके अलावा, के आधार पर पुनः समायोजन किया जाना आवश्यक था

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 और धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा अनुध्यात 2011 की जनगणना के आंकड़े। [पैरा 32] [542-एच; 544-ए-सी]

3.2 . परिसीमन अधिनियम, 2002 में विचार किया गया है -

केवल एक परिसीमन आयोग का गठन और एक से अधिक नहीं। परिसीमन अधिनियम, 2002 को पहली बार जम्मू और कश्मीर राज्य में 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया था। यहां तक कि 1962 और 1972 के परिसीमन अधिनियम भी जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थे। जे एंड के पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर, न केवल के प्रावधान

परिसीमन अधिनियम, 2002 को संघ पर लागू किया गया था।

अधिनियम, 2002 स्वयं इंगित करता है कि धारा 10 की उप-धारा (6) के तहत निर्धारित 31 जुलाई 2008 की समय सीमा पवित्र नहीं है क्योंकि यह माननीय राष्ट्रपति को परिसीमन को स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ परिस्थितियों में किसी राज्य में अभ्यास करना। इस प्रकार, धारा 10 की उप-धारा (6) में दी गई समय सीमा को कभी भी अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा परिसीमन अधिनियम की धारा 2 (च) में संशोधन करते समय, धारा 10 की उप-धारा (6) को प्रदान की गई अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधित नहीं किया गया है।

इसके नीचे। हालाँकि, जम्मू-कश्मीर हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर. की धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) में विधायिका की मंशा परिलक्षित होती है।

वी. भारत संघ और

ओआरएस।

पुनर्गठन अधिनियम एकदम स्पष्ट है। यह तथ्य कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) के अनुसार पुनः समायोजन करने का कर्तव्य सौंपा गया है,

परिसीमन आयोग का सुझाव है कि विधायिका का इरादा था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग आवश्यकता से अप्रभावित रहेगा

जुलाई 2008 के अंत तक अभ्यास पूरा करने के लिए। प्रावधान

के अनुसार बनाए गए कानून में ऐसे प्रावधानों को शामिल करें नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुच्छेद 3, जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी विधि में संसद और राज्य के विधानमंडल या ऐसी विधि से प्रभावित राज्यों में प्रतिनिधित्व के बारे में भी प्रावधान हो सकते हैं। इसलिए, ऐसा कानून जो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया है, हमेशा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का प्रावधान कर सकता है।

परिसीमन आयोग के माध्यम से नवगठित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए, 6 मार्च 2020 के विवादित आदेश के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना से कोई अवैधता जुड़ी नहीं है। [पैरा 35] [545-एफ-एच; 546-ए] [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.5 . 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

जो इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, वे एक वर्ष की अवधि के लिए थे। 3 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि

इसे दो साल तक बढ़ाया गया था। 21 फरवरी 2022 की तीसरी विवादित अधिसूचना द्वारा, दो साल की उक्त अवधि को दो साल और दो महीने तक बढ़ा दिया गया था। एक बार परिसीमन आयोग की स्थापना के बाद, केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है।

परिसीमन/पुनः समायोजन का कार्य पूरा होने तक अध्यक्ष। परिसीमन अधिनियम, 2002 अध्यक्ष की नियुक्ति के कार्यकाल के बारे में चुप है। [पैरा 36] [546-बी-सी]

6 मार्च 2020 की अधिसूचना के दायरे से उत्तर-पूर्वी राज्यों को बाहर करना

4.1 . एक अन्य चुनौती 31 मार्च, 2021 की दूसरी विवादित अधिसूचना के उस हिस्से के लिए है, जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को दंडित किया गया था। 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत गठित परिसीमन आयोग के दायरे से बाहर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उप सचिव (एन. ई.-III) द्वारा 22 फरवरी 2021 को जारी पत्र पर भारत सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में भरोसा व्यक्त किया गया है।

भारत। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 5 और 6 में कहा गया है कि इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को स्थापित परिसीमन आयोग ने पूरे देश के संबंध में परिसीमन की कवायद पूरी कर ली थी।

चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए। यह कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से इन चार राज्यों के परिसीमन को स्थगित कर दिया गया था। परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 ए ने इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने की अनुमति दी। हालाँकि ये चार राज्य 6 मार्च 2020 की अधिसूचना का हिस्सा थे, लेकिन 22 फरवरी 2021 के पत्र में कहा गया है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिसीमन की कवायद के संबंध में इस न्यायालय के साथ-साथ मणिपुर उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ लंबित थीं और न्यायालय के मामलों में विसंगतियाँ थीं। इन राज्यों के संबंध में 2001 की जनगणना के आंकड़ों को इंगित किया गया था। वास्तव में, यह कहा गया है कि हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर को कई नोटिस जारी किए गए हैं।

उक्त विसंगतियों के बारे में। इसलिए, उक्त पत्र सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि यह चार उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिसीमन की प्रक्रिया के लिए विस्तार देने के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। द. 6 मार्च 2020 की पहली विवादित अधिसूचना के तहत गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 मार्च 2021 को समाप्त होना था। उपरोक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष के कार्यकाल को एक वर्ष और बढ़ाते हुए

3 मार्च 2021 की दूसरी विवादित अधिसूचना में उक्त चार राज्यों को बाहर रखा गया था। इस प्रकार, प्रभावी रूप से, 6 मार्च की अधिसूचना के तहत गठित परिसीमन आयोग का कार्यकाल

संविधान के तहत नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की स्थिति और स्थिति चार उत्तर-पूर्वी राज्यों से पूरी तरह से अलग है। संघ पर इसकी प्रयोज्यता में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 और 9 में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजन की आवश्यकता के साथ संशोधन किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में ऐसा कोई संशोधन नहीं है। इसलिए, दो असमानों को बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए, यह तर्क अनुच्छेद 14 सहित संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर आधारित है

अस्वीकार किए जाने योग्य है। [पैरा 37] [546-डी-एच; 547-ए-ई]

4.2 . विद्वान सॉलिसिटर जनरल के तर्क में बहुत सार है कि अधिसूचना को चुनौती दी गई है दिनांक 6 मार्च 2020 को देर से प्रस्तुत करके प्रस्तुत किया गया था

28 मार्च 2022 को याचिका दायर की गई और उक्त देरी के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा, 6 मार्च 2020 की अधिसूचना

परिसीमन की कवायद को पूरा करके काफी हद तक कार्रवाई की गई क्योंकि मसौदा आदेश भी 14 मार्च 2022 को प्रकाशित किया गया था। [पैरा 39] [548-बी]

4.3 . रिट याचिका में, पहली प्रार्थना चुनौती देने के लिए है

सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करना। ने कहा कि प्रावधान धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा किया गया है।

[2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के किसी भी प्रावधान की वैधता को चुनौती देते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने का अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 81 लोक सभा की संरचना से संबंधित है; अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद संसद के सदन के पुनः समायोजन और सीटों के आवंटन से संबंधित है और अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित है। इनमें से कोई भी प्रावधान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ये दोनों प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित नहीं हैं। किसी भी मामले में, यह मानते हुए भी कि अनुच्छेद 332 संघ के विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण पर लागू किया जा सकता है

क्षेत्रों में, यह नहीं दिखाया गया है कि विधानमंडल में सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का कार्य अनुच्छेद 332 का उल्लंघन कैसे करेगा, जब तक कि अनुच्छेद 332 के तहत प्रदान किए गए सूत्र के अनुसार आरक्षण बनाए रखा जाता है। [पैरा 40] [548-सी-एफ]

4.4 . एक अन्य तर्क यह दिया जाना चाहिए कि नए विधानमंडल में 114 सीटों के लिए प्रावधान किया गया है।

गठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर अवैध है। इस प्रस्तुति पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) की वैधता को कोई चुनौती नहीं है। [पैरा 41] [548-जी]

4.5 . एक अन्य तर्क दिया गया कि परिसीमन

निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 2008 के आदेश से विचलित नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन द्वारा किए गए परिसीमन को पुनः प्रस्तुत करता है

जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 1976 और 1995 के संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आदेश। 1976 और 1995 के दोनों आदेशों को जम्मू-कश्मीर द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है। पुनर्गठन अधिनियम धारा 11 (4) और 14 (5) के आधार पर जैसा कि दूसरी और तीसरी अनुसूचियों में प्रावधान किया गया है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए। [पैरा 42] [548-एच; 549-ए-बी] हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर.

बी. भारत संघ और

ओआरएस।

लोक सभा में सीटों के वितरण और विधानसभा को आवंटित सीटों को 2011 की जनगणना के आधार पर फिर से समायोजित करना होगा और वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करना होगा। धारा 63 का प्रभाव यह है कि एक बार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजन/परिसीमन किया जाता है, इसे संबंधित आंकड़ों तक रोक दिया जाएगा।

2026 के बाद की गई पहली जनगणना उपलब्ध है। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन/पुनः समायोजन की कवायद परिसीमन द्वारा की जानी आवश्यक थी

4.7 . महान्यायवादी की राय पर रखा गया भरोसा गलत है क्योंकि यह केवल ए. पी. के प्रावधानों से संबंधित है। पुनर्गठन अधिनियम, 2014। याचिकाकर्ता लोकसभा में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यह अनुच्छेद 170 के संदर्भ में तेलंगाना में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। किसी भी स्थिति में, उक्त राय के साथ-साथ माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

जे एंड के पुनर्गठन अधिनियम की व्याख्या। [पैरा 44] [549-एफ जी]

4.8 . याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत करने का एक अस्पष्ट प्रयास किया गया था कि यह अभ्यास जो नवगठित संघ के लिए किया गया है

पुनर्गठन अधिनियम, 2014। दोनों अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ समान सामग्री है जिसने प्रावधानों [2023] 5 एस. सी. आर. में संशोधन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिसीमन अधिनियम 2002 की नवगठित पर इसकी प्रयोज्यता में

वर्ष 2001 को 2011 से प्रतिस्थापित करके केंद्र शासित प्रदेश। [पैरा 45] [549-जी-एच; 550-ए]

4.9 . किसी भी विवाद में कोई दम नहीं है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया। फैसले में दिए गए निष्कर्ष इस आधार पर हैं कि संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) और (3) के तहत वर्ष 2019 में की गई शक्ति का प्रयोग वैध है। उक्त शक्तियों के प्रयोग की वैधता का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं का विषय है। इसलिए, इस न्यायालय ने वैधता के मुद्दे पर विचार नहीं किया है। इस निर्णय में कही गई किसी भी बात को संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) और (3) के तहत शक्तियों के प्रयोग को अनुचित नहीं माना जाएगा। [पैरा 46] [550-बी-सी]

इंजीनियरिंग कामगर यूनियन बनाम। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग,

भारत, 1967 (2) एससीआर 109; मेघराज कोठारी बनाम।
परिसीमन आयोग और अन्य। , 1967 (1) एससीआर 400 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 9 (जी)

संदर्भित किया गया है

2004 (6) एससीसी 36

पैरा 9 (आर)

1967 (2) एससीआर 109

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (एफ)

संदर्भित किया गया है

1967 (1) एससीआर 400

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं।

237 2022 तक।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रविशंकर जंघ्याला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सनी कुमार, श्रीराम पी., अधिवक्ता।

याचिकाकर्ताओं के लिए।

तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, एएसजी, शैलेश मडियाल, कानू

अग्रवाल, सुश्री नीला केदार गोखले, सौरव राँय, नकुल चेंगप्पा के. के., सुश्री आकृति ए. मनुबरवाला, पार्थ
अवस्थी, वैभव सभरवाल, सुधांशु प्रकाश, सुश्री विनायक एस. पंडित, राजन परमार, अक्षय कुमार,
अरविंद कुमार शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री तरुणा अर्धेन्दुमाउली प्रसाद, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री
पल्लवी बरुआ, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका में मुख्य चुनौती की कार्रवाई की वैधता और वैधता है

परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन का अभ्यास।

प्रासंगिक तथ्य

2. सी. ओ. No.272 वाला संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019 भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था। 5 अगस्त 2019 को। उक्त आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। उक्त आदेश में निर्देश दिया गया है कि संविधान के सभी प्रावधान, समय-समय पर संशोधित, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे, जो अनुच्छेद 367 में किए गए संशोधनों के अधीन होंगे।

आदेश दिया। उक्त आदेश द्वारा, खंड (4) को अनुच्छेद 367 में जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि "राज्य की संविधान सभा" पद का उल्लेख किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के परंतुक में खंड (2) को "राज्य की विधान सभा" के रूप में पढ़ा जाएगा। 6 अगस्त को

2019 , संसद की सिफारिश पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के तहत एक घोषणा की गई थी, जिसके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।

3. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (संक्षेप में, 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम') अधिनियमित किया गया था जिसमें

पूर्ववर्ती राज्य में कारगिल और लेह जिलों के क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (संक्षेप में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर) का गठन किया गया था जिसमें कारगिल और लेह जिलों के अलावा मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। इसकी धारा 13 के आधार पर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 ए, जो पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर लागू होता था, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गया। अनुच्छेद 239 ए संसद को केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल बनाने के लिए एक कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. परिसीमन अधिनियम, 2002 जो इन पर लागू नहीं था -

पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 के आधार पर लागू किया गया था। 6 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। आयोग की अध्यक्षता इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने की थी। चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त को परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया था। अध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष निर्धारित किया गया था। दिनांक 3 मार्च 2021 की एक अधिसूचना द्वारा, इससे पहले

परिसीमन आयोग की नियुक्ति के लिए 6 मार्च 2020 की अधिसूचना में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को परिसीमन आयोग के दायरे से हटा कर संशोधन किया गया था। उसी अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष का कार्यकाल दो साल तक बढ़ा दिया गया था। 6 मार्च 2020 की अधिसूचना में और संशोधन किया गया।

21 फरवरी 2022 की एक अधिसूचना द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष का कार्यकाल दो साल और दो महीने के लिए होगा।

5. उप-जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 की धारा (1) में प्रावधान है कि संघ की विधानसभा में सीटों की संख्या

जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र 107 से बढ़ाकर 114 किया जाएगा। धारा 14 की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें खाली रहेंगी और विधानसभा की कुल सदस्यता की गणना के लिए इन्हें ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

दुआएँ

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का आह्वान करते हुए वर्तमान रिट याचिका में बहुत व्यापक और व्यापक प्रार्थना की गई है। सबसे पहले

चुनौती केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि के प्रावधान के लिए है। दूसरी चुनौती अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के दायरे से हटाकर 6 मार्च 2020 की अधिसूचना में किए गए संशोधन के लिए है। परिसीमन आयोग। तीसरी चुनौती 6 तारीख की अधिसूचना के तहत परिसीमन आयोग के गठन के लिए है

मार्च 2020। चुनौती इस आधार पर है कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 (संक्षेप में हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर.) के बाद।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

" 2008 का परिसीमन आदेश ") भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था, मौजूदा परिसीमन आयोग को समाप्त कर दिया गया था और

इसलिए नए परिसीमन आयोग का गठन अनुचित और अवैध था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत भारत के चुनाव आयोग (संक्षेप में, चुनाव आयोग) के अधिकार क्षेत्र को हड़पकर की गई है और इसलिए परिसीमन का गठन किया गया है।

आयोग जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (2) और (5) के प्रावधानों के अधिकार से बाहर था। अनुच्छेद 170 के खंड (3) के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर परिसीमन आयोग के गठन को भी चुनौती दी गई है। 7. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि 13 मई 2022 को इस न्यायालय ने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रविशंकर जंध्याला का निवेदन दर्ज किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर हमला नहीं करना चाहते हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अभिवचनों में उस ओर से लगाए गए कुछ आरोपों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि चुनौती वास्तव में परिसीमन के संबंध में की गई कवायद के लिए थी

6 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार जिसमें आगे संशोधन किया गया है

3 मार्च 2021 और 21 फरवरी 2022 की अधिसूचनाएँ। 8. भारत संघ द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 5 मई 2022 को,

परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप-धारा (2) और धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आदेश है।

और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यह भी बताया गया है कि 20 मई 2022 के एक और आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने शक्तियों का प्रयोग किया

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) के तहत 20 मई 2022 को उस तारीख के रूप में नियुक्त किया गया है जिस दिन पर परिसीमन आयोग द्वारा जारी 5 मई 2022 का आदेश लागू होगा। जवाबी हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इससे पहले, परिसीमन आयोग द्वारा 14 मार्च 2022 को एक मसौदा आदेश प्रकाशित किया गया था जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रस्ताव थे, और इसके लिए आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। चुनाव द्वारा 5 मई 2022 और 20 मई 2022 की अधिसूचनाओं/आदेशों की प्रतियां रिकॉर्ड में रखी गई हैं।

आयोग-प्रत्यर्थी सं। 5 . [2023] 5 एस. सी. आर. द्वारा दायर एक प्रत्युत्तर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत संघ द्वारा दायर जवाबी हलफनामों से निपटने वाले लोग
चुनाव आयोग।

याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ

9. श्री रविशंकर जंध्याला, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ताओं के लिए रिंग ने विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं। सारांश
प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

कि अनुच्छेद 170 के खंड (3) का दूसरा परंतुक

(अ)

संविधान में कहा गया है कि जब तक वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक 1971 की जनगणना और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के आधार पर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या को फिर से समायोजित करना आवश्यक नहीं होगा, जैसा कि 2001 की जनगणना के आधार पर फिर से समायोजित किया जा सकता है। द.

परिसीमन/पुनः समायोजन का अभ्यास

संघ की विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

परिसीमन की नियुक्ति करके J & K का क्षेत्र

6 मार्च 2020 की विवादित अधिसूचना के तहत आयोग अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे परंतुक का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 82 का तीसरा परंतुक 1971 की जनगणना के आधार पर लोक सभा में सीटों के आवंटन के पुनः समायोजन और राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है।

2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है।

2026 के बाद की गई पहली जनगणना उपलब्ध है।

इससे पहले, प्रतिबंध पहले के आंकड़ों तक लागू था।

(ख)

वर्ष 2000 के बाद की गई जनगणना उपलब्ध थी। इसे संविधान (84 वां संशोधन अधिनियम, 2001) द्वारा वर्ष 2000 के लिए वर्ष 2026 को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया था। द.

सरकार उद्देश्यों और कारणों को कमजोर नहीं कर सकती

उक्त संशोधन;

वर्ष के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़ों तक

(ग)

2026 उपलब्ध होने पर, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या समान रहती है।

जी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास अवैध और अनावश्यक था।

(घ)

हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने वैधता को चुनौती नहीं दी होगी
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 के अनुसार,
संविधान के अनुच्छेद 170 के खंड (3) का उल्लंघन और
इसलिए, धारा 62 के प्रावधान इस प्रकार नहीं हो सकते हैं -
लागू किया गया। उन्होंने कहा कि संख्या
राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्र कर सकते हैं

केवल अनुच्छेद 170 और विशेष रूप से, उसके खंड (3) के दूसरे परंतुक के अनुसार और
इसलिए, निर्वाचन क्षेत्रों का कोई भी पुनः समायोजन करने का कोई प्रयास।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का संविधान अनुच्छेद 170 का उल्लंघन करता है। द.
संघ की विधान सभा का गठन

वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़े तैयार होने तक जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र वही
रहना चाहिए

उपलब्ध है;

(ई)

अनुच्छेद 82 और 83 को ध्यान में रखते हुए, सदन के निर्वाचन क्षेत्र
वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के परिणामों के प्रकाशन के बिना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-
कश्मीर के लोगों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है।

(+)

विद्वान महान्यायवादी द्वारा दी गई राय

कार्यान्वयन के संबंध में 6 जुलाई 2016 को भारत

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 26 (संक्षेप में, '2014 अधिनियम') बहुत
प्रासंगिक है। भारत के विद्वान महान्यायवादी ने राय दी कि 2014 के अधिनियम की धारा 26 और
संविधान के अनुच्छेद 170 के बीच टकराव था और इसलिए, अनुच्छेद 170 प्रबल होगा। यह था।

प्रस्तुत किया कि उक्त राय प्रासंगिक को नियंत्रित करेगी

जे एंड के पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान भी;

(जी)

एक कानून में एक गैर-अवरोधक खंड ओवरराइड नहीं कर सकता है

संविधान के प्रावधान। इंजीनियरिंग कामगर के मामले में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था।

यूनियन वी. इस ओर से 'इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग';

चुनाव द्वारा प्रकाशित 2008 का परिसीमन आदेश

(ज)

आयोग से विचलन नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश इस संबंध में बहुत प्रासंगिक हैं।

[2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 के तहत,

((i)

परिसीमन का काम चुनाव आयोग को सौंपा गया है, 6 मार्च 2020 की अधिसूचना जो परिसीमन आयोग को उक्त कार्य करने की अनुमति देती है।

व्यायाम, पूरी तरह से अवैध है;

यह एक स्थापित कानून है कि यह न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है

((ii)

संसद के सदनों की कार्यवाही। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ तेलंगाना राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में एक माननीय सदस्य द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने 3 अगस्त 2021 को दिया था।

सवाल यह था कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या को पहले सत्र के बाद फिर से समायोजित किया जाएगा।

जनगणना वर्ष 2026 के बाद प्रकाशित की जाती है।

किसी भी स्थिति में, परिसीमन की नियुक्ति

(के)

6 मार्च 2020 के आदेश के तहत आयोग है

जो प्रावधान करता है कि परिसीमन आयोग होगा जल्द से जल्द गठित किया गया। उप-धारा 10 की धारा (6)

परिसीमन अधिनियम, 2002 में परिसीमन की आवश्यकता है

उप-धारा 10 की धारा (6); परिसीमन अधिनियम, 2002 संविधान पर विचार करता है।

(1)

आयोग। अतः वह निवेदन करेगा कि परिसीमन आयोग का गठन पूरी तरह से

अवैध;

(एम) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के दायरे से अवैध रूप से बाहर रखा गया था। उक्त कार्रवाई की गई थी

22 फरवरी 2021 के पत्र के आधार पर

गृह मंत्रालय के उप सचिव द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि लंबित मुकदमों पर विचार करते हुए जे. आई. अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन अभ्यास के संबंध में, परिसीमन अभ्यास उक्त राज्यों में नहीं किया जाना चाहिए। पहले की अधिसूचना को उप सचिव के विचारों के आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता है। भारत संघ और चुनाव आयोग अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मानदंड लागू नहीं कर सकते हैं। 6 मार्च 2020 की अधिसूचना में शामिल अन्य राज्यों को बाहर करने का कोई कारण नहीं था।

(एन)

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 59 से 63 नहीं हैं

केवल संविधान के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है लेकिन एक दूसरे के विरोधाभासी भी है। ये धाराएँ चुनाव आयोग दोनों को परिसीमन की शक्ति प्रदान करती हैं।

और परिसीमन आयोग जो ये बनाता है

धाराएँ पूरी तरह से अवैध हैं। उप-परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 की धारा (1) (बी) चुनाव की अनुमति देती है।

परिसीमन में वर्णित सीमा, क्षेत्र या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार में कोई भी बदलाव करने के लिए आयोग

पहले से जारी और प्रकाशित आदेश;
शब्दों को हटाने का कार्य "लेकिन इसमें शामिल नहीं है

(0)

जम्मू और कश्मीर राज्य "धारा 2 (च) से

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

भारत का संविधान;

सभी परिसीमन आदेशों का समेकन पहले ही किया जा चुका था

(पी)

निर्वाचन आयोग द्वारा धारा 9 के अनुसार

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950;

(9)

संविधान के अनुच्छेद 2 से 4 अन्य के अधीन हैं।

संविधान के प्रावधान और उक्त अनुच्छेदों के प्रावधान संवैधानिक योजना पर हावी नहीं हो सकते हैं; और

5 मई 2020 और 20 मई के आदेशों के बावजूद

(आर)

उप के तहत शक्तियों के प्रयोग में मई 2022 पारित किया गया

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की धारा (1), वर्तमान रिट याचिका बनाए रखने योग्य है। का निर्णय

मेघराज कोठारी बनाम के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठा परिसीमन आयोग और Ors.² होगा

वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं।

[2023] 5 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्टभारत संघ के मिशन

श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल

या भारत संघ ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

रिट याचिका में देरी और अड़चनों का सामना करना पड़ता है

विवादित द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया था

अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2020। यह थी अधिसूचना
किया गया संशोधन

राज्यों को हटाकर 3 मार्च 2021 को

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड। इसके बाद, 14 मार्च 2022 को आयोग द्वारा परिसीमन आदेश का एक मसौदा प्रकाशित किया गया। 28 मार्च 2022 तक, वर्तमान याचिका दायर की गई है। 6 मार्च 2020 की अधिसूचना को चुनौती देने के लिए, वर्तमान रिट याचिका दो साल से अधिक समय के अंतराल के बाद दायर की गई है।

इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, परिसीमन आदेश

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत परिसीमन आयोग द्वारा जारी किया गया है जिसे 20 मार्च 2022 से लागू किया गया है। परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (2) के तहत, धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत पारित आदेश पर सवाल उठाने वाले किसी भी न्यायालय पर पूरी तरह से रोक है। मेघराज कोठारी 2 के मामले में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, की उप-धारा (2) के तहत प्रतिबंध

धारा 10 अनुच्छेद 226 के तहत एक उपाय पर भी लागू होती है।

संविधान से। अनुच्छेद 329 भी एक प्रतिबंध बनाता है

किसी भी कानून की वैधता के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आदेश को एक कानून माना गया है और इसलिए अब 5 मई 2020 और 20 मई के आदेश दिए गए हैं।

2022 पूछताछ नहीं की जा सकती;
62 काम करती हैं।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 और

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और धारा 62 जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। 2011 की जनगणना। उन्होंने बताया कि धारा 60 की उप-धारा (1) जो परिसीमन के चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान करती है, "मई" शब्द का उपयोग करती है जबकि धारा 62 में "होगा" शब्द का उपयोग किया गया है; हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर।

वी. भारत संघ और

ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

चुनाव आयोग ने 2 सितंबर को एक पत्र द्वारा

(ई)

2019 भारत सरकार को सूचित किया कि चूंकि परिसीमन आयोग का गठन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 के तहत किया गया है जो इसे पूरा कर रहा है संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, निर्वाचन आयोग के लिए परिसीमन अधिनियम की धारा 60 के तहत अभ्यास करना आवश्यक नहीं था;

अनुच्छेद 3 विशेष रूप से संसद को कानून द्वारा गठन करने का अधिकार देता है।

(†)

एक नया राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट उक्त कानून को कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में उचित संशोधन का प्रावधान करना चाहिए। अनुच्छेद 4 के खंड (2) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि ऐसी किसी भी कानून को एक कानून नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए संविधान का संशोधन
368. मंगल सिंह और अन्न के मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था। वी. संघ का

भारत 3 3 इस ओर से; और

अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 170 के खंड (3) इन पर लागू नहीं होते हैं -

(जी)

केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल भी।

रेजेंडर

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्युत्तर के तरीके में आग्रह किया गया कि हालांकि जम्मू-कश्मीर के प्रावधानों की वैधता के लिए वर्तमान याचिका में कोई विशिष्ट चुनौती नहीं हो सकती है

पुनर्गठन अधिनियम, उक्त चुनौती का हमेशा अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संवैधानिक प्रावधानों और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के बीच असंगति के मुद्दों का जवाब भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा नहीं दिया गया है।

प्रस्तुतियों का समावेश

जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित घटनाक्रम

वर्ष 2019 में

12. (क) 5 अगस्त 2019 को संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 (संक्षेप में '2019 राष्ट्रपति आदेश') को माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था।

3 1967 (2) एससीआर 109 [2023] 5 एससीआर

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति।
उक्त आदेश सरकार की सहमति से जारी किया गया था जम्मू और कश्मीर राज्य। 2019 के
राष्ट्रपति आदेश के खंड (2) में प्रावधान किया गया है कि सभी प्रावधान

भारत के संविधान का, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध
में उक्त आदेश में निर्धारित अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के
संबंध में अनुच्छेद 367 में उक्त आदेश द्वारा खंड (4) जोड़ा गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि

" संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के परंतुक में खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा को
"राज्य की विधान सभा" के रूप में पढ़ा जाएगा। 2019 का राष्ट्रपति आदेश लाया गया था

तत्काल प्रभाव से लागू;

दूसरा महत्वपूर्ण विकास संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के तहत संसद की सिफारिश पर माननीय
राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा (संक्षेप में 'उक्त घोषणा') थी। यह घोषणा की गई थी कि 6 अगस्त 2019 से
अनुच्छेद 370 के सभी खंड उक्त घोषणा में शामिल अपवादों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे। यह था।

बशर्ते कि अनुच्छेद 152 और 308 के साथ-साथ संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू और कश्मीर के
संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी कानून में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, समय-
समय पर संशोधित भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।

इस प्रकार, 2019 के राष्ट्रपति के आदेश और उक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, 6 अगस्त 2019 से
भारत के संविधान के सभी प्रावधान लागू हो गए।

2019 के राष्ट्रपति आदेश में दिए गए संशोधनों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू। उक्त घोषणा
और 2019 के परिणामस्वरूप

राष्ट्रपति का आदेश, अनुच्छेद 370 के आधार पर संविधान के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा
वस्तुतः समाप्त हो गया; एल गनी खान और एएनआर।

वी. भारत संघ और

ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का अधिनियमन था जिसे 9 अगस्त 2019 को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को नियत किया गया था। इसकी धारा 3 और 4 के आधार पर 31 अक्टूबर 2019 से एक नया केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया जिसे संघ के नाम से जाना जाता है। लद्दाख का क्षेत्र। उक्त केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह जिले शामिल हैं। नियत दिन से, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी बनाया गया था। उक्त केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर को भी अस्तित्व में लाया गया।

परिसीमन अधिनियम, 2002 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गया क्योंकि इसकी धारा 2 के खंड (च) में "राज्य" की परिभाषा में विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा, कई अन्य केंद्रीय अधिनियमों को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की तालिका 1 में शामिल किया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गया;

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'आर. पी. अधिनियम 1951') संसद के किसी भी सदन में सीटों को भरने के लिए होने वाले चुनावों पर लागू नहीं था।

दोनों नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू किए गए थे। इससे पहले, जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 (संक्षेप में "जम्मू-कश्मीर आर. पी. अधिनियम") राज्य में लागू था। हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (संक्षेप में '1950 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम'), [2023] 5 एस. सी. आर. पर लागू था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जम्मू और कश्मीर राज्य, यही बात दो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है;

(छ) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13 के आधार पर, अनुच्छेद 239 ए में निहित प्रावधान जो पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू होते थे।

पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था। अनुच्छेद 239 ए, अन्य बातों के साथ, प्रदान करता है कि

संसद कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय का निर्माण कर सकती है।

J & K के प्रावधानों की वैधता का मुद्दा

पुनर्गठन अधिनियम। 13. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों की सुनवाई के दौरान,

उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता पर हमला करने का प्रयास किया। इसलिए, हमने उन्हें बताया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के किसी भी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को वर्तमान रिट याचिका में कोई चुनौती नहीं दी गई है। वरिष्ठ वकील की प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह थी कि वह प्रावधानों को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा कि

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को चुनौती देना इस रिट याचिका में निहित है।

14. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जब कोई पार्टी चाहे

अभिवचनों में चुनौती के विशिष्ट आधारों को शामिल करके विशेष रूप से चुनौती दी गई। इसका कारण यह है कि कानूनों की संवैधानिकता की धारणा हमेशा बनी रहती है। इसे साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो असंवैधानिकता का आरोप लगाता है। उस उद्देश्य के लिए, चुनौती का विशेष रूप से उन विशिष्ट आधारों को निर्धारित करके अनुरोध किया जाना चाहिए जिन पर चुनौती दी गई है। एक संवैधानिक न्यायालय एक सक्षम विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में केवल इन दलीलों से निष्कर्ष निकालकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि वैधता को चुनौती निहित है। राज्य को कानून की रक्षा करने का उचित अवसर तभी मिलता है जब राज्य उन आधारों से अवगत कराया जाता है जिनके आधार पर कानून को चुनौती दी जानी चाहिए।

हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

15. हालाँकि याचिकाकर्ताओं के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने का अवसर उपलब्ध था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। हम यहां यह भी नोट कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता 2019 के राष्ट्रपति के आदेश और उक्त घोषणा पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसलिए, हमें 2019 के राष्ट्रपति के आदेश, उक्त घोषणा और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के प्रावधानों के आधार पर आगे बढ़ना होगा अधिनियम वैध हैं। यह इस संदर्भ में है कि बार में की गई प्रस्तुतियों की सराहना करनी होगी।

रिट याचिका में चुनौतियों पर निष्कर्ष

16. संविधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्पष्ट अंतर करता है जैसा कि अनुच्छेद 1 और पहली अनुसूची से देखा जा सकता है। संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 का अध्याय 2

संसद से निपटें। भाग VI राज्यों से संबंधित है। भाग VI का अध्याय III राज्य विधानमंडल से संबंधित है। संविधान का भाग VIII केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है।

स्पष्टीकरण I में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 3 के खंड (ए) से (ई) में, एक "राज्य" में "केंद्र शासित प्रदेश" शामिल है। इस प्रकार, स्पष्टीकरण I यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 3 के खंड (ए) के तहत संसद की शक्ति, एक नया राज्य बनाने के लिए कानून बनाने या किसी राज्य की सीमा को बदलने की शक्ति में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति शामिल है। स्पष्टीकरण II स्पष्ट करता है कि खंड (ए) द्वारा संसद को एक नया राज्य बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 4 के खंड (1) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 3 में प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी भी कानून में पहली अनुसूची (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची वाली) और चौथी अनुसूची (राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन वाली) के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों। इस तरह के एक कानून में यह भी शामिल हो सकता है कि संसद में और राज्य के विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के प्रावधानों सहित पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान या ऐसे कानून से प्रभावित राज्य जो संसद आवश्यक समझे। अनुच्छेद 4 का खंड (2) स्पष्ट करता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है

अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। उसी कानून द्वारा, संसद और संघ के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के बारे में एक प्रावधान किया जा सकता है [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के कानून द्वारा बनाया गया क्षेत्र। मंगल सिंह 3 के मामले में संविधान पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 4 के तहत शक्ति इतनी व्यापक है कि विधानसभा के कुल सदस्यों को अनुच्छेद 170 के खंड (1) द्वारा निर्धारित न्यूनतम से भी कम किया जा सकता है।

18. सबसे पहले, हम अनुच्छेद की प्रयोज्यता के मुद्दे से निपटेंगे।

170 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए "विधानसभाओं की संरचना" शीर्षक रखने वाला अनुच्छेद 170 "राज्य विधानमंडल" शीर्षक के तहत अध्याय III का हिस्सा है। अध्याय III को संविधान के भाग VI में शामिल किया गया है जो राज्यों से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे प्रावधान में निहित प्रावधानों के उल्लंघन पर बहुत जोर दिया गया था। लेकिन हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि उक्त अनुच्छेद से संबंधित नहीं है।

केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के साथ बिल्कुल भी। अनुच्छेद 239 ए और 239 एए जो संविधान के भाग VIII में शामिल हैं, वे अनुच्छेद हैं जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका और मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय के निर्माण से संबंधित हैं। सुविधा के लिए, हम अनुच्छेद 239 ए को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार है:

" 239 ए. स्थानीय विधानमंडलों या परिषदों का निर्माण

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्री या दोनों-(1)
संसद कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए बना सकती है

[पुडुचेरी]

(क) एक निकाय, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित, संघ के लिए एक विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए क्षेत्र, या

(ख) मंत्रिपरिषद, या ऐसे संविधान के साथ दोनों, शक्तियाँ

और प्रत्येक मामले में कार्य, जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट कोई ऐसी विधि नहीं मानी जाएगी।

अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन होना

368 इसके बावजूद कि इसमें कोई प्रावधान है जो संशोधन करता है या इस संविधान में संशोधन का प्रभाव है।

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 239 ए, जैसा कि यह मूल रूप से था, प्रदान करता है कि संसद

कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश या मंत्रिपरिषद या दोनों के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय का निर्माण करें। अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत आने वाले केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए ऐसा निकाय निर्वाचित या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित किया जा सकता है।

हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13 के आधार पर, 31 अक्टूबर 2019 से अनुच्छेद 239 ए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गया। जैसा कि अनुच्छेद 239 ए के खंड (2) में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 239 ए के खंड (1) द्वारा अनुध्यात कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके बावजूद कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान है जो संविधान में संशोधन करता है या जिसका प्रभाव संविधान में संशोधन करने पर पड़ता है।

19. अनुच्छेद 3,4 और 239 ए के संयुक्त पठन पर हम पाते हैं कि:

संसद कानून बनाकर किसी मौजूदा राज्य को परिवर्तित कर सकती है।

अ)

एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में;

संसद को कानून द्वारा एक निकाय बनाने का अधिकार है -

ख)

पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल। तदनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए एक विधानसभा होगी। ; और

भले ही संसद द्वारा बनाया गया कानून एक निकाय का निर्माण करता है

(ग)

संविधान के कुछ भागों में संशोधन का प्रभाव है, तो इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान।

20. अब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि उक्त कानून संसद द्वारा शक्तियों के प्रयोग में बनाया गया है

अनुच्छेद 3,4 और 239 ए के तहत। उक्त कानून ने जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थान पर दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। उक्त कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है। धारा 13 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इसे लागू करने के लिए अनुच्छेद 239 ए में संशोधन का प्रावधान करती है।

संसद द्वारा किए गए पूरक और परिणामी प्रावधान

बनाया गया है। उप-धारा (3) में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों की संख्या 107 होगी। उप-धारा [2023] 5 एस. सी. आर. का खंड (ए)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) धारा 14 में प्रावधान है कि उक्त केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 24 सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र पर कब्जा करना बंद नहीं हो जाता। हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के संविधान के तहत, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए निर्धारित 24 सीटों को छोड़कर राज्य विधानसभा में 87 सीटें थीं, जिनमें से 7 सीटें थीं -

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 22. जहाँ तक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का सवाल है, हमें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के भाग V का भी उल्लेख करना चाहिए जिसका शीर्षक है -

" निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन "। धारा 60 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। हालाँकि, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से बाहर की गई 24 सीटें वही हैं। इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए अब उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 90 है।

23. इसलिए, जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का संबंध है, अनुच्छेद 170 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह

भाग VI के अध्याय III का भाग जो केवल राज्य विधानमंडल से संबंधित है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों पर लागू नहीं होता है। इसका कारण यह है कि संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं अनुच्छेद 239 ए के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा शासित होंगी, न कि भाग VI के अध्याय III के प्रावधानों द्वारा। चूंकि अनुच्छेद 170 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विधानमंडल पर लागू नहीं होता है, इसलिए इस तर्क का मुख्य जोर कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कुछ प्रावधान और उसके तहत की गई कार्रवाई अनुच्छेद 170 और विशेष रूप से खंड (3) के साथ टकराव में हैं, स्पष्ट रूप से गलत धारणा है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

परिसीमन का अभ्यास

24. अब, हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर आते हैं। परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित दो पूर्व अधिनियम। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 और दूसरा परिसीमन अधिनियम, 1972 था। दोनों अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थे क्योंकि दोनों अधिनियमों में शामिल राज्य की परिभाषा में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था। परिसीमन अधिनियम, 2002 का भी यही हाल है। हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर आर. पी. अधिनियम की धारा 3 ने हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर. को निर्धारित किया है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

परिसीमन आयोग की स्थापना की आवश्यकता जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि परिसीमन आयोग विधान सभा में सीटों को एकल सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित करेगा।

और उप में उल्लिखित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए उनका परिसीमन करें।

धारा 3 की धारा (2)। जम्मू-कश्मीर आर. पी. अधिनियम की धारा 4-बी ने परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में एक आदेश पारित करने और उसे प्रकाशित करने का प्रावधान किया। वास्तव में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1995 जारी किया गया था जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू था। जम्मू-कश्मीर आर. पी. अधिनियम की धारा 4-सी ने चुनाव आयोग को परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश में किसी भी मुद्रण गलती या किसी भी त्रुटि या चूक को ठीक करने की शक्ति प्रदान की। चुनाव आयोग को किसी भी जिले या किसी भी जिले की सीमाओं या नामों में संशोधन करने का भी अधिकार था।

परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश में उल्लिखित क्षेत्रीय विभाजन को बदल दिया गया था।

25. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (5) के आधार पर 1995 के उक्त परिसीमन आदेश में संशोधन किया गया था

जैसा कि इसकी तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में धारा 14 की उप-धारा (3) में दिए गए कुल 107 में से मौजूदा 83 विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में 1995 के उक्त परिसीमन आदेश द्वारा किए गए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में किए गए संशोधनों का विवरण है। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आने वाले 24 निर्वाचन क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिसीमन आदेश के दायरे में नहीं थे।

इस प्रकार, धारा 14 की उप-धारा (5) के आधार पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के 83 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को तीसरी अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था जो नए व्यक्तिगत 83 निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ और उनमें शामिल क्षेत्र।

26. अब हम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के भाग V पर आते हैं जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के आधार पर, परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था

31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। सुविधा के लिए, हम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 से 63 को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार है:

60. (1) इस अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

107 से 114 तक, और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा इसके बाद दिए गए तरीके से निर्धारित किया जा सकता है।

संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा; (ख) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिनमें केंद्र शासित प्रदेश विभाजित किया जाएगा, उनमें से प्रत्येक का विस्तार

निर्वाचन क्षेत्र और उनमें से कौन सी सीटें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी; और (ग) प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और विस्तार के विवरण में समायोजन जो आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट मामलों का निर्धारण करने में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: (क) सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होंगे।

(ख) सभी निर्वाचन क्षेत्र, जहां तक संभव हो, भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय, भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाओं और जनता के लिए सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा; और

(ग) जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, जहां तक संभव हो,

यह उन क्षेत्रों में स्थित है जहाँ कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।

उप-धारा (1) के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में, सहयोगी सदस्यों के रूप में खुद को संबद्ध करते हुए, चार व्यक्ति केंद्रीय के रूप में सरकार आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के सदस्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के चार सदस्य हैं:

बशर्ते कि किसी भी सहयोगी सदस्य को मतदान करने या चुनाव आयोग के किसी भी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

अजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

(4) यदि मृत्यु या त्यागपत्र के कारण किसी सहयोगी सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, तो इसे उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, जहां तक संभव हो, भरा जाएगा। (5) चुनाव आयोग करेगा

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करें।

किसी भी सहयोगी सदस्य के असहमत प्रस्ताव, यदि कोई हो, जो आधिकारिक राजपत्र में इसका प्रकाशन चाहता है और इस तरह के अन्य तरीके से जो आयोग उचित समझे, प्रस्तावों के संबंध में आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ और एक तारीख निर्दिष्ट करता है जिसके बाद इसके द्वारा प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा।

(ख) उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करें जो इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से पहले प्राप्त हुए हों; और (ग) इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से पहले प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, एक या अधिक आदेशों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और कारण निर्धारित करें।

राजपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे आदेश या आदेश, और वहाँ ऐसे प्रकाशन पर, आदेश या आदेश कानून के पूर्ण बल में होंगे और किसी भी अदालत में प्रश्न में नहीं बुलाए जाएंगे।

(6) इस तरह के प्रकाशन के बाद जितनी जल्दी हो सके, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित प्रत्येक आदेश विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या आदेश में उल्लिखित किसी क्षेत्रीय विभाजन की सीमाओं या नाम में परिवर्तन किया जाता है या किया जाता है, वहां ऐसे संशोधन करें जो ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। (2) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इस धारा के तहत प्रत्येक अधिसूचना, इसे जारी किए जाने के तुरंत बाद, विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62. (1) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत आदेशों के प्रकाशन या उक्त धारा की उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, परिसीमन अधिनियम, 2002 को नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा:

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, शब्द और आंकड़ा "वर्ष 2001 में आयोजित जनगणना", जहां भी हो, को शब्द और आंकड़ा "वर्ष 2011 में आयोजित जनगणना" के रूप में माना जाएगा। (2) जम्मू और कश्मीर के उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेश में धारा 60 के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्व्यवस्थापन, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, और यह ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार,

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

(3) जम्मू और कश्मीर के उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेश में धारा 11 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन

63. विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन के संबंध में विशेष प्रावधान। - धारा 59 से 61 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जब तक वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक उत्तराधिकारी संघ के विभाजन को फिर से समायोजित करना आवश्यक नहीं होगा। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर का राज्यक्षेत्र और इस भाग में "नवीनतम जनगणना आंकड़ों" के किसी भी संदर्भ को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

(जोर दिया गया)

हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

27. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के 83 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था और

धारा 60 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से खंड (सी) द्वारा प्रदान किया जाएगा परिसीमन आयोग द्वारा किया गया। तथापि, धारा 62 की उप-धारा (2) निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन को संदर्भित करती है। लेकिन, धारा 62 की उप-धारा (2) का तात्पर्य यह है कि पुनः समायोजन का अर्थ है नव स्थापित केंद्र शासित प्रदेश में 90 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण। इस प्रकार, की उप-धारा (2) द्वारा विचार की गई पुनः समायोजन की प्रक्रिया

धारा 62 और कुछ नहीं बल्कि धारा 60 की उप-धारा (1) के तहत परिसीमन का प्रयोग है।
28. यदि हम परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों को देखते हैं, तो यह इंगित करता है कि पुनः समायोजन क्या है। धारा 4 इस प्रकार है:

" 4. आयोग के कर्तव्य। (1) पुनः समायोजन किया गया,

गठित परिसीमन आयोग द्वारा वर्ष 1971 में आयोजित जनगणना में निर्धारित जनगणना के
आंकड़ों के आधार पर
परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 3 के तहत, कई राज्यों को लोक सभा में सीटों
के आवंटन [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और प्रत्येक विधान सभा में सीटों की कुल संख्या
जाएगा

राज्य द्वारा किया गया पुनः समायोजन माना

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग।
के अधीन रहते हुए

(2) उप-धारा (1) और किसी अन्य के प्रावधानों

उस समय लागू कानून के अनुसार, आयोग

प्रत्येक राज्य के विभाजन को क्षेत्रीय में पुनः समायोजित करें

जनता और राज्य विधान सभा को

जनगणना में निर्धारित जनगणना के आंकड़ों का आधार

वर्ष [2001] में आयोजित:

बशर्ते कि जहां इस तरह के पुनः समायोजन पर केवल एक सीट है

लोक सभा में किसी राज्य को आवंटित किया गया, वह पूरा
निर्वाचन क्षेत्र बनाएगा -

राज्य इस उद्देश्य के लिए एक क्षेत्रीय

उस राज्य से लोक सभा के लिए चुनाव "।

(जोर दिया गया)

ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपखंड (बी) के आधार पर

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, वर्ष 2001 की धारा 62 के (1) पर

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के संबंध में वर्ष 2011 तक प्रतिस्थापित।

29. परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 के तहत, एक विशिष्ट शक्ति

परिसीमन आयोग को निटेशन अभ्यास आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया। धारा 9 इस प्रकार है:

" 9. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। — (1) आयोग ने

प्रत्येक राज्य को आवंटित लोक सभा में सीटें

और प्रत्येक की विधान सभा को सौंपे गए स्थान

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य और उन पर परिसीमन
आंकड़ों के आधार पर

जनगणना में निर्धारित जनगणना के

वर्ष [2001] में आयोजित, के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

संविधान, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान और

निम्नलिखित प्रावधान, अर्थात्:

(क) सभी निर्वाचन क्षेत्र, जहां तक व्यावहारिक हो, भौगोलिक रूप से होंगे।

सघन क्षेत्र, और उनका परिसीमन करने में ध्यान देना होगा

भौतिक विशेषताएँ, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाएँ,

संचार और सार्वजनिक सुविधा की सुविधाएँ; हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर।

वी. भारत संघ और

ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

(ख) प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह गिर जाए।
पूरी तरह से एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर;

(ग) वे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं।

जातियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया जाएगा और स्थित किया जाएगा, जहाँ तक संभव हो, उन क्षेत्रों में जहाँ उनका अनुपात

कुल जनसंख्या तुलनात्मक रूप से बड़ी है; और

(घ) वे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं।
जनजातियाँ, जहाँ तक संभव हो, उन क्षेत्रों में स्थित होंगी जहाँ

कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे बड़ा है।

(2) आयोग करेगा

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करें, किसी भी सहयोगी के असहमत प्रस्ताव, यदि कोई हो, के साथ

और सभी संबंधित राज्यों के आधिकारिक राजपत्रों में भी ऐसा अन्य तरीका जो वह उचित समझे;

(ख) एक तारीख निर्दिष्ट करें जिसके बाद प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाएगा।

उसके द्वारा विचार किया गया;

(ग) उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करें जो हो सकते हैं -

इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से पहले उसके द्वारा प्राप्त किया गया, और इसके उद्देश्य के लिए

इस तरह के विचार, ऐसे स्थान पर एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें आयोजित करें

या प्रत्येक राज्य में ऐसे स्थान जो वह उचित समझे; और

(घ) तत्पश्चात एक या अधिक आदेशों द्वारा निर्धारित किया जाता है

((i) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन; और
((ii) प्रत्येक राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।

(जोर

दिया गया)

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, की उप-धारा (1) के खंड (ख) के आधार पर

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62, वर्ष 2001 में

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 की उप-धारा (1) को 2011 के रूप में पढ़ना होगा। इसलिए, 6 मार्च 2020 के आदेश के तहत स्थापित परिसीमन आयोग को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन या पुनः समायोजन का अभ्यास करना पड़ा क्योंकि पूर्ववर्ती राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अभ्यास 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नहीं किया गया था। ऊपर बताए गए कारणों से, [2023] 5 एस. सी. आर. के अभ्यास के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश को 90 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग द्वारा किए गए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन/पुनः समायोजन। 30. परिसीमन आयोग की नियुक्ति की वैधता के मुद्दे से निपटने से पहले, हमें संसदीय मुद्दों से निपटना चाहिए

नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निर्वाचन क्षेत्र। 1950 के आर. पी. अधिनियम की पहली अनुसूची में, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को कुल 6 सीटें आवंटित की गई थीं, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि पूर्ववर्ती राज्य को आवंटित 6 सीटों में से 5 सीटें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को आवंटित की जाएंगी और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दी जाएगी। इस प्रकार धारा 11 में यह प्रावधान है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार संशोधित किया गया है। इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन दूसरी अनुसूची में प्रदान की गई धारा 11 के आधार पर किया गया था। 31. हम पहले ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 का हवाला दे चुके हैं। उसकी उप-धारा (1) के खंड (सी) में प्रावधान है कि विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि पर विचार करते हुए,

प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और विस्तार के विवरण में समायोजन चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। धारा 62 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन जैसा कि धारा 11 में दिया गया है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेश होंगे -

परिसीमन आयोग द्वारा किया गया। पुनः समायोजन का उल्लेख किया गया है। धारा 62 की उप-धारा (3) में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का समायोजन और विस्तार का विवरण है जैसा कि धारा 60 की उप-धारा (1) में दिया गया है। विधानसभा के 90 निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन/परिसीमन की आवश्यकता के परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया। इसलिए, इससे कोई अवैधता जुड़ी नहीं है। परिसीमन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन/पुनः समायोजन।

परिसीमन की नियुक्ति की वैधता

6 मार्च 2020 की अधिसूचना द्वारा आयोग

32. परिसीमन आयोग का गठन करने वाली 6 मार्च 2020 की विवादित अधिसूचना इस प्रकार है:

अजी अब्दुल गनी खान और एएनआर। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

" कानून और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

सूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

एस. ओ. 1015 (ई)। - परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से परिसीमन आयोग का गठन किया है।

(i) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई-अध्यक्ष ((ii) श्री सुशील चंद्र,

चुनाव आयुक्त

- सदस्य, (पदेन)

(iii) अनुच्छेद 243 के खंड (1) के तहत नियुक्त संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त या

2. न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति। रंजना प्रकाश देसाई आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा,

((i) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में

जम्मू के भाग 5 के प्रावधानों के अनुसार

& कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) और

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के प्रावधान।

((ii) असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और

परिसीमन के प्रावधानों के अनुसार नागालैंड
2002 (2002 का 33) "

अधिनियम,

(जोर दिया गया)

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब उक्त अधिसूचना की आवश्यकता होती है

परिसीमन आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अभ्यास करने के लिए, यह धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) में प्रदान किए गए पुनर्व्यवस्थापन के अभ्यास को संदर्भित करता है जो कि धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा अनुध्यात परिसीमन अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं है।

विधान सभा की सदस्यता 83 से बढ़ाकर 90 करना। इसके अलावा, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजन करना आवश्यक था, जैसा कि परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 और धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा अनुध्यात किया गया था, जैसा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा संशोधित किया गया था।

33. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि

परिसीमन अधिनियम, 2002 में केवल एक के गठन पर विचार किया गया है

केवल परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा और संसद दोनों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का अनिवार्य कर्तव्य परिसीमन आयोग को सौंपा गया था। धारा 62 की धारा (2) और (3)। 31 अक्टूबर 2019 तक, परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना नहीं की जा सकती थी क्योंकि उक्त अधिनियम तब तक जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया था।

34. परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (6)

इस प्रकार पढ़ता है:

" 10. आदेशों का प्रकाशन और उनके संचालन की तारीख।

XXX

XXX

XXX

(6) आयोग प्रत्येक को पूरा करने और प्रकाशित करने का प्रयास करेगा। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उसके आदेशों का उपबंधित तरीके से

उस उप-धारा में, [31 वें दिन के बाद की अवधि के भीतर]

जुलाई, 2008] धारा 3 के तहत।
उप-धारा (6) में "प्रयास" शब्द का उपयोग किया गया है। धारा 10 ए

परिसीमन अधिनियम, 2002 स्वयं इंगित करता है कि 31 जुलाई 2008 की समय सीमा हाजी अब्दुल गनी खान और एएनआर।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

धारा 10 की उप-धारा (6) के तहत निर्धारित करना पवित्र नहीं है क्योंकि यह माननीय राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में किसी राज्य में परिसीमन की कवायद को स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, धारा 10 की उप-धारा (6) में प्रदान की गई समय सीमा को कभी भी अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा परिसीमन अधिनियम की धारा 2 (च) में संशोधन करते समय, धारा 10 की उप-धारा (6) को उसके तहत प्रदान की गई अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधित नहीं किया गया है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) में विधायिका की मंशा स्पष्ट है। तथ्य यह है कि धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) के अनुसार पुनः समायोजन करने का कर्तव्य

35. संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 संसद को नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करने में सक्षम बनाते हैं। तदनुसार, दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जिसने दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया, के पुनर्संतुलन की भूमिका निर्धारित करता है। परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत परिसीमन आयोग के निर्वाचन क्षेत्र। संविधान का अनुच्छेद 4 संसद को अनुमति देता है कि -

नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुच्छेद 3 के अनुसार बनाए गए कानून में ऐसे प्रावधानों को शामिल करना, जो -

कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसी विधि में संसद और राज्य के विधानमंडल या ऐसी विधि से प्रभावित राज्यों में प्रतिनिधित्व के बारे में भी प्रावधान हो सकते हैं। इसलिए, ऐसा कानून जो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया है, हमेशा नवगठित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (2023) 5 एस. सी. आर. में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का प्रावधान कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिसीमन आयोग के माध्यम से। इसलिए, हमारा मानना है कि 6 मार्च 2020 के विवादित आदेश के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना से कोई अवैधता जुड़ी नहीं है।

36. 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, जो सेवानिवृत्त थे

इस न्यायालय के न्यायाधीश एक वर्ष की अवधि के लिए थे। 3 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को दो साल तक बढ़ा दिया गया था। के द्वारा

21 फरवरी 2022 की तीसरी विवादित अधिसूचना में दो साल की उक्त अवधि को दो साल और दो महीने तक बढ़ा दिया गया था। एक बार परिसीमन आयोग की स्थापना के बाद, केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है।

परिसीमन/पुनः समायोजन का कार्य पूरा होने तक अध्यक्ष। परिसीमन अधिनियम, 2002 अध्यक्ष की नियुक्ति के कार्यकाल के बारे में चुप है।

6 मार्च 2020 की अधिसूचना के दायरे से उत्तर-पूर्वी राज्यों को बाहर करना

37. एक अन्य चुनौती जो गंभीर रूप से दबाव में है, वह 31 मार्च 2021 की दूसरी विवादित अधिसूचना के उस हिस्से के लिए है जिसके द्वारा

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्य थे -

6 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत गठित परिसीमन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया। भारत सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, उप सचिव (एन. ई.-III), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 फरवरी 2021 को जारी पत्र पर निर्भरता रखी गई है। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 5 और 6 में कहा गया है कि इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को स्थापित परिसीमन आयोग ने चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर पूरे देश के संबंध में परिसीमन की कवायद पूरी कर ली थी। यह कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से इन चार राज्यों के परिसीमन को स्थगित कर दिया गया था। परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 ए ने इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने की अनुमति दी। हालांकि ये चार राज्य 6 मार्च 2020 की अधिसूचना का हिस्सा थे, लेकिन 22 फरवरी 2021 के पत्र में कहा गया है कि कई याचिकाएं दायर की गई थीं

पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन अभ्यास के संबंध में इस न्यायालय के साथ-साथ मणिपुर उच्च न्यायालय में लंबित और न्यायालय के मामलों में, इन राज्यों के संबंध में 2001 की जनगणना के आंकड़ों में विसंगतियों को इंगित किया गया था। वास्तव में, यह कहा गया है कि उक्त विसंगतियों के संबंध में कई नोटिस जारी किए गए हैं। इसलिए उक्त पत्र हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर. था।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

2021 , उक्त चार राज्यों को बाहर रखा गया था। इस प्रकार, प्रभावी रूप से, 6 तारीख की अधिसूचना के तहत गठित परिसीमन आयोग का कार्यकाल मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में केवल एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। तीसरी विवादित अधिसूचना द्वारा, अवधि को दो महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 ए स्वयं कुछ आकस्मिकताओं में परिसीमन के अभ्यास को स्थगित करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, संविधान के तहत नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की स्थिति और स्थिति चार पूर्वोत्तर राज्यों से पूरी तरह से अलग है। इसमें

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू होने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 और 9 में संशोधन किया गया है, जिसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजन करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में ऐसा कोई संशोधन नहीं है। इसलिए, दो असमानों को बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 14 सहित संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर आधारित तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

38. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि परिसीमन का मसौदा आदेश 14 मार्च 2022 को जारी किया गया था। द. अंतिम आदेश 5 मई 2022 को जारी किया गया था जिसे 20 मई 2022 से लागू किया गया था। यह स्वीकार करते हुए कि उसने नहीं किया है

इन बाद के आदेशों को चुनौती देते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता धारा 10 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं जो यह निर्धारित करता है कि ऐसे प्रत्येक आदेश में

विधि का बल और किसी भी न्यायालय में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। वास्तव में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने मेघराज कोठारी 2 के मामले में संविधान पीठ के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि विधायिका का इरादा यह है कि एक बार परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेश को धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसार प्रकाशित किया जाए, तो उन्हें कानून के रूप में माना जाता है, जिस पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पैराग्राफ में 21 उक्त निर्णय के बारे में संविधान पीठ ने कहा कि हालांकि परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 8 और 9 के तहत धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसार पारित आदेश संसद [2023] 5 एस. सी. आर. के किसी अधिनियम का हिस्सा नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेकिन इसका प्रभाव वही रहेगा। किसी भी मामले में, इस याचिका में परिसीमन आयोग के आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया है।

39. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल के तर्क में बहुत सार है कि चुनौती

6 मार्च 2020 की अधिसूचना देर से प्रस्तुत करके दाखिल की गई थी।

28 मार्च 2022 को याचिका और उक्त देरी के लिए, कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा, 6 मार्च 2020 की अधिसूचना पर परिसीमन की कवायद को पूरा करके काफी हद तक कार्रवाई की गई क्योंकि मसौदा आदेश भी 14 मार्च 2022 को प्रकाशित किया गया था।

40. रिट याचिका में पहला अनुरोध सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 करने को चुनौती देने के लिए है। उक्त प्रावधान उप द्वारा किया गया है

धारा 60 की धारा (1)। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के किसी भी प्रावधान की वैधता को चुनौती दिए बिना, यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम सीटों की संख्या बढ़ाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 81 लोक सभा की संरचना से संबंधित है; अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद संसद के सदन के पुनः समायोजन और सीटों के आवंटन से संबंधित है और अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित है। इनमें से कोई भी प्रावधान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ये दोनों प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित नहीं हैं। जो भी हो,

यह मानते हुए कि अनुच्छेद 332 संघ के विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण पर लागू किया जा सकता है

क्षेत्रों में, यह नहीं दिखाया गया है कि विधानमंडल में सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का कार्य अनुच्छेद 332 का उल्लंघन कैसे करेगा, जब तक कि अनुच्छेद 332 के तहत प्रदान किए गए सूत्र के अनुसार आरक्षण बनाए रखा जाता है। 41. एक अन्य तर्क दिया जाना चाहिए कि नवगठित संघ के विधानमंडल में 114 सीटों के लिए प्रावधान किया गया है।

जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र अवैध है। इस प्रस्तुति पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) की वैधता को कोई चुनौती नहीं है।

42. एक अन्य तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित 2008 के परिसीमन आदेश से विचलित नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यह परिसीमन हाजी अब्दुल गनी खान और ए. एन. आर. को पुनः प्रस्तुत करता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 1976 और 1995 के संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेशों द्वारा बनाए गए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। 1976 और 1995 के दोनों आदेशों को जम्मू-कश्मीर द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है।

पुनर्गठन अधिनियम धारा 11 (4) और 14 (5) के आधार पर जैसा कि दूसरी और तीसरी अनुसूचियों में प्रावधान किया गया है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

43. याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (बी) ने परिसीमन अधिनियम, 2002 में यह प्रावधान करके और संशोधन किया है कि परिसीमन अधिनियम में दिखाई देने वाले शब्द और आंकड़े 'वर्ष 2001 में आयोजित जनगणना' को 'वर्ष 2011 में आयोजित जनगणना' के रूप में माना जाएगा। इसके आवेदन के लिए

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, वर्ष 2001 में परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 की उप-धारा (1) को वर्ष 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और इसलिए, लोक सभा में सीटों और विधानसभा को आवंटित सीटों के वितरण को 2011 की जनगणना के आधार पर फिर से समायोजित करना होगा और परिसीमन वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। धारा 63 का प्रभाव यह है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजन/परिसीमन का अभ्यास किए जाने के बाद, 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े उपलब्ध होने तक इसे रोक दिया जाएगा। इसलिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन/पुनः समायोजन की कवायद की आवश्यकता थी। धारा 63 को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ों के प्रकाशन के बाद ही आगे का समायोजन किया जा सकता है

वर्ष 2026 के बाद की गई जनगणना से।

44. भारत के विद्वान महान्यायवादी की राय पर रखा गया भरोसा गलत है क्योंकि यह केवल ए. पी. के प्रावधानों से संबंधित है।

पुनर्गठन अधिनियम, 2014। याचिकाकर्ता लोकसभा में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यह अनुच्छेद 170 के संदर्भ में तेलंगाना में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। किसी भी मामले में उक्त राय के साथ-साथ माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर का जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं किया गया था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के आधार पर किया गया। दोनों अधिनियमों में 5 एस. सी. आर. (2023) हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई किसी भी दलील में कोई दम नहीं है। हालाँकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि निष्कर्ष निर्णय में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) और (3) के तहत वर्ष 2019 में की गई शक्ति का प्रयोग वैध है। हम जानते हैं कि उक्त शक्तियों के प्रयोग की वैधता का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं का विषय है। इसलिए, हमने वैधता के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। इस निर्णय में कही गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) और (3) के तहत शक्तियों के प्रयोग को हमारी प्राथमिकता देता है।

47. इसलिए, रिट याचिका को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

लिखित

याचिका खारिज कर दी गई।

बिभूति भूषण बोस

(सहायक: वरुण धोंड, एलसीआरए)